

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1068

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

सोने की कीमतों में वृद्धि

1068. श्री बी. मणिकम टैगोर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- क) क्या सरकार ने सोने की कीमतों को विनियमित करने और कृत्रिम मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं;
- ख) विगत वर्ष के दौरान सोने की कीमतों में 40 प्रतिशत की वृद्धि से प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की क्या योजना है;
- ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ती कीमतों के बावजूद सोने की खरीद जारी रखे हुए है और यदि हां, तो आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?;
- घ) उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए सोने पर आयात शुल्क को कम करने के संबंध में सरकार का क्या रुख है;
- ङ) सोने के मूल्य निर्धारण में सरकार किस प्रकार पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी तथा गुटबाजी को रोकेगी;
- च) सुरक्षित निवेश आस्तियों की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक निवेश विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे;
- छ) क्या सरकार ने सोने की कीमतों में वृद्धि का विवाह के मौसम और त्यौहारों की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और
- ज) क्या सरकार सोने की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए मूल्य नियंत्रण या सब्सिडी लागू करने की कोई योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में सोने के आयात पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था।

(ग) आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ सोने के सिक्कों और बुलियन की खरीद और बिक्री शामिल है। सोना विदेशी मुद्रा भंडार का एक भाग है। अमेरिकी डॉलर की स्थिति अनुसार 31 मार्च, 2023 में सोना, विदेशी मुद्रा भंडार का 7.81 प्रतिशत और 31 मार्च, 2024 में 8.15 प्रतिशत था। यह बदलाव अर्जन के अतिरिक्त मूल्य निर्धारण संबंधी बदलावों के कारण है। आरबीआई द्वारा सोने की खरीद मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजारों में होती है और इसका स्वदेशी बाजार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

(घ) सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए सोने को अधिक वहनीय बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में सोने पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ड) भारतीय मानक ब्यूरो हालमार्क वाले आभूषण की शुद्धता सुनिश्चित करता है जो पारदर्शिता और ग्राहक के विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), कार्टेलीकरण सहित प्रतिस्पर्धा-विरोधी पद्धतियों को रोकने हेतु प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू करता है। जब कभी कार्टेलीकरण पद्धति संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सीसीआई इस अधिनियम के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करता है।

(च) हाल के वर्षों में वित्तीय आस्तियों में निवेश का क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। वित्तीय क्षेत्र विनियामक विभिन्न वित्तीय लिखतों में निवेश अवसरों के संबंध में निवेश शिक्षण और जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां कार्यान्वित करते हैं।

(छ) और (ज): यद्यपि सरकार सोने की कीमतों की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है, तथापि सरकार ने त्यौहारों के अवसर पर बढ़ती मांग से सोने की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया है। सरकार ने सोने के संबंध में मूल्य नियंत्रण अथवा सब्सिडी कार्यान्वित करने हेतु किसी विशिष्ट योजना की घोषणा नहीं की है।

\*\*\*\*\*